भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3422
जिसका उत्तर मंगलवार 7 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

विद्युत वाहनों पर राजसहायता हेतु मानदण्ड

3422. डॉ कंभमपति हरिबाबू:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत चालित वाहनों पर राजसहायता निर्धारण हेतु अर्थात, बैटरी पैक के आकार के उपयोग हेतु मानदंडों के संबंध मे सरकार के समक्ष कोई चिंता व्यक्त की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार राजसहायता प्रदान करने हेतु अन्य मापदंडों जैसे कि उनकी उच्चतम गति और एक बार की चार्ज में रेंज इत्यादि जैसे मापदंडों को भी शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): अपनी परामर्शी प्रक्रिया में सरकार को समय-समय पर उद्योगों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। सभी स्टेकहोल्डरों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते समय ऐसे सभी अभ्यावेदनों को शामिल किया जाता है।

****